मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा व नगरीय विकास की समीक्षा की

राजस्थान को, पीएम ई-बस सेवा योजना में 125 अतिरिक्त बसें मिलेंगी- खट्टर

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने पीक आवर्स में बिजली की माँग की आपूर्ति के लिये माँग के अनुरूप विद्युत आवंटन में बढ़ोतरी के लिये केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केन्द्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें।

जयपुर, 29 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर केन्द्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केन्द्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें।

शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हम राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कॉमन पूल से प्रदेश को आवंटित अस्थायी विद्युत कोटे के रूप में सहयोग देने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया।

शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की पीक आवर्स में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली के आवंटन में बढ़ोतरी का आग्रह किया, जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में, खासतौर से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, राज्य में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।

पीएम कुसुम योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है।

नगरीय विकास विभाग की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में सीवरेज अनिवार्य रूप से हो तथा आवश्यकतानुसार पुराने और जर्जर सीवरेज को बदलने तथा एलाइनमेंट ठीक करने के कार्य भी किए जाएं। बैठक में पीएम ई-बस सेवा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत राजस्थान को 675 बसों का प्रारम्भिक आवंटन हुआ था। राज्य सरकार के अनुरोध पर अब इसके लिए केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 125 बसें भी दी जाएंगी, जिससे शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा को मजबूती मिलेगी। इस दौरान जयपुर मेट्रो परियोजना, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित, विभिन्न योजनाओं की राज्य में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर सहित, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

जस्टिस बीआर गवई 52 वें सीजेआई नियुक्त

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को मंगलवार को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति गवई 14 मई को सीजेआई का पदभार संभालेंगे। मौजूदा सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जस्टिस गवई

- 13 मई को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जस्टिस गवई 14 मई से कार्यभार संभालेंगे।

उनकी जगह लेंगे। कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका नाम 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना द्वारा केंद्र सरकार को सिफारिश के रूप में भेजा गया था। जस्टिस गवई का कार्यकाल छह महीने का होगा और वह 23 दिसंबर को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे।

'सेना तय करे कार्यवाही का तरीका, समय और टारगैट'

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही के लिए सेना को खुली छूट दी

- मंगलवार को प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ उच्चस्तरीय मीटिंग की, जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, एन.एस.ए. अजीत डोभाल भी थे।
- इसके बाद प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की। यही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री से मिलने आए।

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, पीएम ने स्पष्ट किया कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में मंगलवार एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख शामिल थे। बैठक में पहलगाम हमले की विस्तृत समीक्षा की गई और आतंकवाद के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अलग से मीटिंग की। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजी सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इसके बाद संघ संचालक मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने पहुंचे।

बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक भी हो सकती है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीसीएस की बैठक में सेना के ऑपरेशनल प्लान और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत इस हमले का जवाब न केवल त्वरित, बल्कि इतना प्रभावी देगा कि आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट संदेश मिले।

ट्रम्प प्रशासन ने एमेज़ॉन को "धमकी"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

57,000 लोगों को निकाल दिया है, क्योंकि मॉल और बाजारों में ग्राहक कम हो गए हैं और उपभोक्ता भावना कमजोर हुई है।

टैक्नॉलजी सेक्टर, जो अमेरिका की सफलता का स्तंभ रहा है, भी सिकुड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन के पहले सौ दिनों में ही इस क्षेत्र से चालीस हज़ार से अधिक लोगों की छंटनी हो चुकी है। आम अमेरिकियों में इसके खिलाफ व्यापक आक्रोश और विरोध व्याप्त है।

कुछ जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। यहाँ तक कि उनके सत्ता ग्रहण करने के बाद से रेटिंग्स में बहुत कमी आई है। इतना ही नहीं, जिन आम मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया था, वे अब अपने फैसले पर पछता रहे हैं, मुख्यत: बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण।

हालांकि, अब भी ट्रंप के कट्टर समर्थक, खासकर श्वेत वर्चस्ववादी समूह, मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां दीर्घकाल में अमेरिका के हित में हैं।

कई लोग खुश हैं कि वर्षों पहले बंद हो चुकी पुरानी इंडस्ट्रीज फिर से लौट सकती हैं। लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि एक बार जो इंडस्ट्री बंद हो गई, उसे दोबारा खड़ा करना बेहद मुश्किल होता है, खासकर अब, जबकि अमेरिका की इन्डस्ट्री का इकोसिस्टम पूरी तरह बदल चुका है।

यदि इन्हें पुन: जीवित किया गया तो कई उद्योग बहुत पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इन उद्योगों के लिए जरूरी पुर्जे अब देश में उपलब्ध नहीं हैं और श्रम लागत इतनी अधिक है कि उत्पादन आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रह गया है। फिर भी उम्मीद बनी हुई है कि ये उद्योग फिर से फलेंगे-फूलेंगे।

रेलवे भर्ती परीक्षा में पैन, पैंसिल, पानी पर प्रतिबंध

रेल मंत्रालय ने रेल भर्ती बोर्ड के सभी अध्यक्षों को सर्कुलर जारी किया

- परीक्षार्थी सिर्फ ई कॉल लैटर के साथ ही आ सकेंगे, पैन भी उन्हें परीक्षा हॉल में ही उपलब्ध करवाया जाएगा।

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल। भारतीय रेलवे ने रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में इलेक्ट्रोनिक सामान के अलावा पेन, पेंसिल, टोपी, पर्स एवं पानी की बोतल लाने को भी प्रतिबंधित कर दिया है और हाथों पैरों में मेहंदी लगा कर आने पर भी रोक रहेगी।

रेल मंत्रालय ने सभी रेल भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों में संशोधन किया गया है। इसमें परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की नयी सूची जारी की गई है।

उम्मीदवारों को दिए गए निर्देशों के पैरा 7(1) में कहा गया है कि प्रतिबंधित वस्तुएं/इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर, घड़ियां, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त डिवाइस, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, पुस्तक, पेन, कागज, पेंसिल, ई-यूजर, पाउच, स्केल, राइटिंग-पैड, बेल्ट, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैक/खुले खाद्य पदार्थ आदि परीक्षा केन्द्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

परिपत्र के अनुसार परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर की अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र के अंदर कोई पेन/पेंसिल नहीं ले जाना है। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेंहदी न लगाएं, क्योंकि इससे बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने में बाधा आती है।

परिपत्र में कहा गया है कि पैरा 7(2) के तहत तलाशी के दौरान, धातु के वस्त्र, धार्मिक प्रतीक, चूड़ियाँ, आभूषण, मंगल सूत्र, कंगन ले जाते/पहने हुए पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को उनके कॉल लेटर में उपयुक्त पुष्टि के साथ परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थियों के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहें।

रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

लोक गायिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया, जो काफी वायरल हुआ, खासकर पाकिस्तान में।

वीडियो में उन्होंने भारत में धार्मिक आधार पर एकता की कमी के बारे में बात की। हिंदी भाषा के इस वीडियो में उन्होंने कहा कि देश धार्मिक आधार व अन्य मुद्दों पर काफी विभाजित है, दंगे भड़कने में एक सैकेण्ड का समय भी नहीं लगेगा। उन्होंने देश के अन्य भागों में रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा की अपील की। उन्होंने कहा कि न्याय किया जाना चाहिए, बदला नहीं।

राठौड़ व काकोती, दोनों को ही सैक्शन 196 के विभिन्न उपभागों में गिरफ्तार किया गया है, जो जन्म, जाति, जन्म स्थान, आवास व नागरिकता, भाषा आदि के आधार पर दो समुदायों में नफरत बढ़ाने से सम्बंधित हैं।

मीडिया विशेषज्ञों का मत है कि सरकार द्वारा जो सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, वे नाकाफी हैं, उनके उल्टे परिणाम हो सकते हैं। सरकार के पास दुष्प्रचार ने निपटने के कई प्रभावी तरीके हैं और ताकत का इस्तेमाल आउट डेटेड हो गया है।

राजस्थान में तेज गर्मी और लू का प्रकोप

मौसम विभाग ने दो मई से गर्मी में राहत की भविष्यवाणी की

- मौसम विभाग के अनुसार एक मई से आंधी-बारिश का दौर शुरु होगा। तेज अंधड़ और बारिश होने से तापमान में कमी आएगी।

जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी हैं और राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक हैं। हालांकि एक मई से आंधी एवं बारिश की गतिविधियों के कारण दो मई से लू में राहत मिलने की संभावना हैं।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस जबकि पूर्वी राजस्थान में 40 से 45 डिग्री के मध्य दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में बाड़मेर के अलावा जैसलमेर में 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा जबकि फलौदी में 45.2, कोटा में 44.6, जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ में 44.4, वनस्थली में 44.2, श्रीगंगानगर में 43.8, बीकानेर एवं जालोर में 43.4, भीलवाड़ा में 43.2, चुरु एवं अलवर में 42.2, उदयपुर के डबोक में 42.1, जयपुर में 42, पाली में 41.9, सीकर 40, धौलपुर में 41, डूंगरपुर में 41.1, सिरोही में 41.4, फतेहपुर में 40.2, करौली 40.9, झुंझुनूं में 40.1, माउंटआबू में 32.4, चुरु 42.2, नागौर 41.5 तथा प्रतापगढ़ एवं सांगरिया में 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान डूंगरपुर में 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 48 घंटों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने एवं तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के कुछ भागों में लू का दौर एक मई तक जारी रहने की संभावना है। एक मई को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तीव्र मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, तेज झोंकेदार हवाएं एवं अंधड़ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की प्रबल संभावना है।

इसके बाद दो और तीन मई को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर एवं भरतपुर संभाग के कुछ भागों में गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं तेज अंधड़ आने और बारिश होने की प्रबल संभावना है। आंधी-बारिश की गतिविधियां चार से सात मई को भी राज्य के कुछ भागों में जारी रहने की आशंका है। आंधी-बारिश के प्रभाव से तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज होने एवं दो मई से लू से राहत मिलने के संभावना है।

कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नगर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कराने का प्रावधान है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट भी पूर्व में तय कर चुका है कि व्यापक जनहित को देखते हुए पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए।

इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित कर उनमें प्रशासक लगा दिए। याचिका में साल 2019 का हवाला देते हुए कहा गया कि तत्कालीन नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले नवंबर माह में ही चुनाव प्रक्रिया आरंभ की गई थी। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह इन नगरपालिकाओं का चुनाव कार्यक्रम घोषित करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

'सफल इकोनॉमिक्स, सफल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विरोधी सोच भी पनप रही है तथा, विशेष रुप से भ्रष्टाचार के आरोपों पर दो मंत्रियों को हटाये जाने के बाद, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार की नकारात्मक छवि भी बनी है। उल्लेखनीय है कि उक्त मंत्रियों को हटाये जाने का कदम अदालतों तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के दबाव के चलते उठाया गया था। और अब एक अन्य मंत्री पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तथा राजनैतिक हल्कों में ऐसी चर्चाएं हैं कि इस तीसरे मंत्री को भी बर्खास्त किया जायेगा।

लेकिन द्रमुक के लिये सौभाग्य का विषय यह है कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार चुनाव हारने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। अन्नाद्रमुक प्रमुख स्व. जयललिता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिनमें वे बाद में दोषी भी सिद्ध हुईं, लेकिन तमिलनाडु के मतदाताओं ने उन्हें लगातार दो बार विजयी बनाया तथा 2011 एवं 2016 के दो लगातार चुनावों में जीतकर, वे एक लम्बी राजनैतिक परम्परा को तोड़ने में सफल हुईं।

इस बात को स्टालिन भी जानते हैं कि द्रमुक जब भी सत्ता से बाहर हुई है, जो हर तीसरे चुनाव में हुआ है, तो उसका बड़ा कारण कानून-व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति, तथा सरकार एवं द्रमुक के गुंडों की मनमानी ही रही है। यही कारण है कि स्टालिन चुनावों से पहले अर्थव्यवस्था पर फोकस कर रहे हैं तथा ग्रोथ एवं समृद्धि के इर्द-गिर्द ही नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अपनी इस उपलब्धि पर विशेष जोर देने के लिये वे उत्तर भारत के राज्यों तथा तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था के बीच तुलना करते हुये, इनके बड़े अन्तर की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "अभी तक, आपने द्रविड मॉडल सरकार पार्ट 1 देखा है। पार्ट 2 वर्ष 2026 में लोड होगा। उसके बाद, हम और नये रिकॉर्ड बनायेंगे।"

कांग्रेस के पोस्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यू-ट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया अकाउन्ट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दी है और कई शीर्ष पाकिस्तानी समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें डॉन न्यूज़, ए.आर.वाय. न्यूज़, समा टीवी और जियो न्यूज़ शामिल हैं।

इन्टरनैट सामग्री की निगरानी करने वाले अधिकारियों का कहना है कि कुछ पाकिस्तान-आधारित सोशल मीडिया हैंडल, खासकर विदेशों में रहने वाले लोगों को निशाना बनाकर, ब्रेनवॉश करने वाली सामग्री डालते हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय राय को प्रभावित किया जा सके। सरकार के सूत्रों ने कहा कि इस तरह के प्रयासों का उद्देश्य पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है।

इज़रायल की रणनीति से प्रेरणा लेते हुए, भारत सरकार भी एक वीडियो श्रृंखला जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ लंबे समय से जारी आतंकवादी हमलों को उजागर किया जाएगा। गाज़ा संघर्ष के दौरान, इज़रायल ने हमास की बर्बरता को उजागर करने के लिए वीडियो जारी किए थे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा है, "यह एक व्यापक युद्ध है, जो बंदूकों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, नैरेटिव्स और धारणाओं के ज़रिए लड़ा जा रहा है।"

कोटा में एक और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर दिया है। छात्र मूल रूप से बिहार के कटिहार का निवासी है। वह 15 दिन पहले ही कोटा आया था और 11वीं के साथ मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। वह अपने एक साथी के साथ रूम शेयर करके रहता था। उन्होंने बताया कि दूसरा लड़का डिनर के लिए चला गया था। जब वापस आया तो छात्र ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उसने हॉस्टल मालिक को बताया। दोनों को शक हुआ तो उन्होंने इस संबंध में तुरंत पुलिस को सूचना दी। हॉस्टल रूम का दरवाजा तोड़कर देखा तो सभी के होश उड़ गए। छात्र को आनन-फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मृतक के चाचा घटना की जानकारी के बाद कोटा पहुंच गए। उनका कहना था कि छात्र के पिता हृदय रोग से ग्रसित हैं। उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के ही शव की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा था कि कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं चाहते हैं। इसके बाद, जवाहर नगर थाना पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का कहना था कि बालक अपनी इच्छा से ही कोटा पढ़ने आया था। उसने अपना स्कूल में एडमिशन गांव में ही करवाया था।

क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले की पीट-पीट कर हत्या

बेंगलुरु, 29 अप्रैल। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने मंगलवार को बताया कि मंगलुरु में एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान एक व्यक्ति की कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने पर दर्शकों में आक्रोश फैल गया और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

पुलिस ने घटना के सिलसिले में करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब व्यक्ति को मैच के दौरान कथित तौर पर नारे लगाते हुए सुना गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि लोगों के एक समूह ने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की और मौके पर ही उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। शुरू में माना जा रहा था कि व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, लेकिन बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि पीड़ित चोटों के कारण सदमे में था बाद में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनाओं के क्रम का पता लगाने और नारे के दावे की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए जांच चल रही है। मृतक की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है।

हाई कोर्ट ने 36 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को मिली सजा को हाईकोर्ट अप्रैल, 1989 में ही स्थगित कर चुका है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अनीस ने बताया कि 13 जुलाई, 1987 को खान मोहम्मद ने माणक चौक थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि रात करीब एक बजे अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई फूल मोहम्मद पर एसिड फैंका, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जिस पर अदालत ने 31 मार्च, 1989 को याचिकाकर्ता को हत्या के प्रयास के अपराध से बरी करते हुए, आईपीसी की धारा 326 के तहत दो साल छह माह की सजा सुनाई गई। इस आदेश के खिलाफ उसी साल हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। वहीं, राज्य सरकार की ओर से भी निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दी गई सजा की अवधि को बढ़ाने की गुहार की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया और मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश अपील भी खारिज कर दी।

राफेल गिराने का पाकिस्तान का दावा झूठा

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल। भारत ने पाकिस्तान समर्थित अनेक सोशल मीडिया खातों में भारतीय वायु सेना के एक लड़ाकू विमान को गिराये जाने के दावे को करार दिया और कहा है कि यह भ्रामक तथा निराधार दुष्प्रचार है और भारत का कोई विमान नहीं गिराया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अनेक सोशल मीडिया खाते झूठा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारत के राफेल लड़ाकू विमान को गिरा दिया है।

- भारत सरकार ने कहा, पाकिस्तान द्वारा जिस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का वीडियो दिखाया जा रहा है वह राफेल नहीं बल्कि जून 2024 में महाराष्ट्र में दुर्घटनाग्रस्त सुखोई विमान का वीडियो है।

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के किसी लड़ाकू विमान को नहीं गिराया है। पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया खातों में जो वीडियो साझा किया जा रहा है वह जून 2024 में महाराष्ट्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए सुखोई-30 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का है।

मुंबई के स्क्वायर मॉल में आग से 100 दुकानें जलीं

मुंबई, 29 अप्रैल। मुंबई से लगे बांद्रा में स्क्वायर मॉल बिल्डिंग में मंगलवार सुबह 4.10 बजे आग लगी, जो शाम तक नहीं बुझाई जा सकी। घटना को 16 घंटे बीत चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 के करीब दुकानें जल चुकी हैं। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में 4 मंजिला मॉल के बेसमेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी थी। जो धीरे-धीरे चौथे फ्लोर तक पहुंची। फायर ब्रिगेड को सबसे पहले सुबह 4.50 बजे आग की सूचना मिली थी। पहले इसे लेवल 3 की आग घोषित किया गया था।

जम्मू कश्मीर के 50 पर्यटन स्थल बंद

87 पर्यटन स्थलों की सुरक्षा ऑडिट के बाद यह कदम उठाया गया

- गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे।

श्रीनगर, 29 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समूचे केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम 50 रिजॉर्ट्स और पर्यटन स्थलों को 'बंद' कर दिया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पिछले सप्ताह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सभी जिलों में किए गए 87 पर्यटन-स्थलों की व्यापक सुरक्षा ऑडिट के बाद लिया गया है।

पर्यटकों के लिए अब प्रतिबंधित प्रमुख स्थलों में बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर स्थित गुरेज़ घाटी शामिल है जिसने पिछले दशक में हजारों पर्यटकों को आकर्षित किया है। बंद किए गए अन्य प्रमुख स्थलों में बडगाम में यूसमर्ग और दूधपथरी, दक्षिण कश्मीर में अहरबल, कोंसरनाग और वेरीनाग, बारामुल्ला में एलओसी पर कमान पोस्ट और कुपवाड़ा में सुरम्य बंगस घाटी शामिल हैं।

इस बीच श्रीनगर के पुराने शहर स्थित भव्य जामिया मस्जिद में पर्यटकों का जाना निषेध कर दिया गया है। हालांकि पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग के प्रमुख रिजार्ट पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। इन जगहों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

केन्द्र शासित प्रदेश में वन विभाग ने भी पर्यटकों के लिए अपने सभी ट्रैकिंग रूट बंद कर दिए हैं।

पिछले चार वर्षों में स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों तरह के पर्यटक कश्मीर के मैदानों और अल्पाइन ट्रेल्स पर खास तौर पर गर्मियों के ट्रैकिंग सीजन के दौरान आते रहे हैं। हाल के वर्षों में घाटी में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन पहलगाम हमले से पर्यटन उद्योग को गहरा झटका लगा है। पिछले छह दिनों में कई पर्यटक कश्मीर छोड़ चुके हैं जबकि कई अन्य ने कश्मीर की अपनी आगामी यात्रा की योजना रद्द कर दी है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर